>

Title : Resolution regarding steps to ensure availability of drinking water in the country.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before I call Shri Satpal Maharaj to move his Private Members Resolution regarding steps to ensure availability of drinking water in the country, time for discussion of this Resolution has to be allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for the discussion of the Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता हूं।:

> "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और वहां स्वजलधारा वर्द्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाएं सही ढंग से लागू और निगरानी नहीं की जा रही हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाई जाए"

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह बताना चाहूंगा कि हमारा देश भारतवर्ष कच्छ से कामख्या तक और कन्याकुमारी से कैलाश तक फैला हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Shri Satpal Maharaj, we will close at six o'clock.

श्री सतपाल महाराज : यह कांटिन्यू हो जाएगा। उत्तर भारत में हिमालय में हमारे ग्लेशियर्स हैं जो हमारे वाटर-बैंक्स हैं। ग्लेशियर्स से धीरे-धीरे कल-कल निनाद करता हुआ जल रिसता है और हमारी नदियां प्राणवान होती हैं। ये सारी हमारी नदियां हमारे देश की नसें हैं, हमारे देश की तंत्रिकातंत्र हैं और इससे हमारी जल-आपूर्ति होती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जल ही जीवन है लेकिन अगर जल प्रदूषित है तो यह मृत्यु का कारण बन जाएगा। जब मैं इसके बारे में अध्ययन करता रहा तो यह पता चला कि भारत की अधिकांश जनता प्रदूषित जल को पी रही है। यह एक गंभीर समस्या हमारे सामने है। इसमें हमारे विशेषज्ञों की राय है और हमारे एक्सपर्ट्स यह कहते हैं,

Experts say that the total amount of water available on earth has been estimated at 1.4 billion cubic kilometers, enough to cover the planet with a layer of about three km. deep. About 95 per cent of the earth's water is in the oceans, which is unfit for human consumption and other use because of its high salt content; about four per cent is locked in the polar ice caps; and the remaining one per cent constitutes all the fresh water in hydrological cycle including ground water reserves. Only 0.1 per cent is available as fresh water in rivers, lakes and streams, which is suitable for human consumption. This highlights the significance of the need to preserve our fresh water resources.

But the major problem is the quality of surface water in majority of the locations, which is affected by pollutants from various sources such as domestic waste discharges, industrial waste disposal, and other human activities such as bathing, washing and swimming, etc. The UNICEF and the WWF studies identified the prevalence of fluoride and iron deposits or ingress of salt water and other sources affecting water quality of both surface and ground water. The projected demands for the annual requirement of fresh water, both surface and ground water, in the country indicate an estimated forty per cent increase by the year 2025 to that in the year 2000.

Chemical contaminants, namely fluoride, arsenic and selenium pose a very serious health hazard in the country. It is estimated that about seventy million people in twenty States are at risk due to excess fluoride and around ten million people are at risk due to excess arsenic in ground water. Apart from this, increase in the concentration of chloride, TDS, nitrate, iron in ground water is of great concern for a sustainable drinking water programme. All these need to be tackled holistically. With over-extraction of ground water, the concentration of chemicals is increasing regularly.[r53]

Next, I come to drinking water problem in rural India. In India, presently, there is the problem of arsenic in the ground water of Bihar, West Bengal and Assam, fluoride content in Gujarat, Andhra Pradesh, Orissa and Karnataka; and salinity hazard in the East Coast and West Coast of India. High fluoride content above the permissible limit of 1.5 milligram per litre is widespread in the Nawapada

District of Orissa which causes drinking water crisis. Though high iron content does not create any health hazard, yet it makes the water unsuitable for drinking in the mining areas of Joda-Badbil of Orissa. Thus, after delineation of the problematic areas, people have to be made aware of the situation and alternative sources of drinking water need to be found.

महोदय, भारत में प्रदूषित पानी की आपूर्ति के कारण 3.37 करोड़ से अधिक लोग पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 15 लाख से अधिक बच्चे डायरिया के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रदुषण के शिकार भारत के गांव हैं। गांवों में देश की 70 फीसदी आबादी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में पानी की मात्रा कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया यानी खून में कमी का कारण फ्लोराइड प्रदूषण को माना जा रहा है। हम बिना कारण पर ध्यान दिए भारत में विकलांग बच्चों की आबादी को बढ़ा रहे हैं। यह एक ऐसी गंभीर समस्या है, जिसका सरकार को निराकरण करना होगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परम्परा है। यह एक ऐसी परम्परा है, जिसका यदि हम गहराई से, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करें तो इसका यही अर्थ है कि जल के स्रोत को रिचार्ज किया जाए। आज हम जगह-जगह से पानी ले रहे हैं, लेकिन उसे रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वाटर डिपलीशन की समस्या खड़ी हो गई है। जगह-जगह ट्यूबवैल और बोरिंग लगाकर इतना ज्यादा पानी निकाला जा रहा है कि पानी कंटैमिनेटिड हो गया है तथा पानी का अभाव हो गया है और परकुलेशन आफ वाटर समाप्त हो गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परम्परा से यह ज्ञात होता है कि हमें अपनी धरती को रिचार्ज करना होगा और वाटर परकुलेशन को बढ़ाना होगा। सरकार की ऐसी योजना होनी चाहिए, जिससे वाटर परकुलेशन बढ़े, रेन हार्वेस्टिंग हो और पानी की जो भयंकर समस्या इस देश में होने जा रही है, सरकार मिलकर उसका निदान करे। उसके लिए एक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

महोदय, मुझे वह समय याद आता है, जब हमारे भगीरथ ने सगर के पुत्र, जो कि मर गए थे, उनकी प्राण रक्षा और मुक्ति के लिए तपस्या की। तपस्या करने के बाद वह गंगा को धरती पर लाए। धरती पर लाने का क्रम यह दर्शाता है कि सरकार के अंदर भगीरथ की तरह इच्छाशक्ति होगी तो निश्चित रूप में घर-घर में पानी पहुंचेगा, वह पानी जीवनदायिनी होगा और कंटैमिनेटिड वाटर नहीं पहुंचेगा। इसके लिए समस्या को हल करने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। They are: identification and isolation of contamination sources; adoption of latest technologies in order to reduce the waste generation and to treat them effectively; improved and innovative planning of water resources; increased participation of the public, either directly or indirectly in solving the crisis; enhanced co-ordination among the Agencies involved (both Governmental and Non-Governmental) for the cause of the Nation. इसके लिए राष्ट्र की वृहद योजना बनानी होगी, ताकि हम स्वच्छ जल दे सकें। आज देश के अंदर बिसलरी पानी का चलन हो गया है। बिसलरी पानी लोग पी रहे हैं, किंतु आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो प्रदूषित जल है, वह प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है। गांवों में ऐसे भी तालाब हैं जहां एक तरफ जानवर पानी पीता है और एक तरफ गांव का आदमी भी वहां से जल लेकर पानी पीता है। अभी भी हमारे देश के अंदर पीने के पानी की एक समस्या बनी हुई है। मुझे विदेशों में भी जाने का मौका मिला तो वहां यह देखने को मिला कि पीने का पानी अलग एक पाइपलाइन से आता है और वह पानी जिससे आप अपनी बागवानी कर सके, कार धो सकें, या नहा सकें, वह दूसरी पाइपलाइन से आता है। मुम्बई के अंदर भी इसी तरह का सिस्टम है कि पीने का पानी अलग पाइपलाइन से आता है। इस प्रकार की कोई कार्ययोजना बननी चाहिए कि पीने के पानी का स्तर उचित रूप से मेनटेन किया जाए और स्वच्छ पानी लोगों को पीने को मिले क्योंकि जल ही जीवन है। अगर वह पानी प्रदूषित रहा तो वह जीवनदायिनी नहीं होगा, मृत्यु का कारण बन जाएगा। मेरा निवेदन है कि इसके साथ-साथ मेरे उत्तराखंड क्षेत्र में भी पानी की बहुत समस्या है। वहां पर भौगोलिक परिस्थिति परस्पर टकरा रही हैं। सैसमिक जोन है, जिससे धरती के अदंर गर्भीय हरकतें होती रहती हैं और जिनके कारण पानी के स्रोत सूख जाते हैं और पानी के स्रोत सूखने से गांव के अंदर हाहाकार मच जाता है, त्राहि-त्राहि मच जाती है, पानी के लिए लोग हल्ला मचाने लगते हैं। इसके साथ साथ इस समस्या का भी समाधान करना होगा कि हम किस प्रकार से वहां पानी को पहुंचा सके। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टैंकर्स के जरिए सरकार ने कोशिश की है पर टैंकर्स जहां सड़क होगी, वहीं जा पाएंगे। इसके लिए भी एक योजना बनानी होगी ताकि सड़कों का जाल पूरे राज्य के अंदर बिछाया जाए और सुगमता से टैंकर जा सके। टैंकर को भरने के लिए भी एक योजना बनानी होगी ताकि आसानी से टैंकर भर जाए। अगर टैंकर ही दस घंटे में भर रहा है तो कैसे वह जनता तक पानी पहुंचा सकता है?

महोदय, पहाड़ों के अंदर यह बहुत गंभीर समस्या है और उत्तराखंड तो जल का स्रोत रहा है। आज हमारी बड़ी-बड़ी नदियां यमुना जी और गंगा जी हमारे उत्तराखंड से बहकर पूरे देश को पानी दे रही हैं परंतु वहां के जो पहाड़ी एरियाज हैं, आज वे पानी से वंचित हैं। आपने सुना होगा कि टेहरी में एक बहुत विशाल झील बनाई गई। आप देखेंगे कि बड़ी सुंदर झील बनी हुई है। विदेश की बड़ी-बड़ी झील को वह मात देती है पर उस झील को बनाने के लिए जिन गांवों को विस्थापित किया गया, उन गांवों का पुनर्वास किया गया लेकिन आज उसी गांव के लोग पानी के लिए प्यासे तरस रहे हैं।

वहां जो बिजली की योजना बन रही है, वही बिजली दिल्ली को चकाचौंध कर रही है। दिल्ली को लाभ पहुंचा रही है पर वहां के लोग आज भी पानी के लिए वंचित है। इसलिए यह देखना होगा कि उत्तराखंड के अदंर जो पानी की विकट समस्या बन गई है, इसके निदान के लिए एक कार्ययोजना हमें तैयार करनी होगी ताकि हम उत्तराखंड को पानी दे सकें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश गांव सड़कविहीन हैं जिसके कारण वहां के निवासियों को अपनी रोजमर्रा की वस्तुएं लाने के लिए कोसों दूर पैदल चलना पड़ता है और अगर वे बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देते हैं। सड़कें न होने से पेयजल का भी अभाव बना हुआ है जिसके कारण टैंकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए बड़ी विकट स्थिति वहां बन गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर जो मेरा संसदीय

क्षेत्र है, उसके अंदर भ्रमण के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो स्वीकृत मोटर मार्ग हैं, उसमें राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग विशेष रुचि नही ले रहा है जिसके फलस्वरूप या तो स्वीकृत मोटर मार्ग का या तो काम नहीं हो पाया है या फिर निर्माण का काम बड़ी धीमी गति से हो पाया है जिससे कारण क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान है। यही नहीं, जिन मोटर मार्गों पर निर्माण का काम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया गया था, उन पर भी अधिकांश बस सेवाएं नहीं चल पा रही हैं और ये मार्ग त्रुटिपूर्ण स्थिति में अधर में लटके हुए हैं। इसलिए जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत देवप्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण इसी योजना के अन्तर्गत 30 जून 2006 को पूरा कर दिया गया था। किंतु अभी तक इस मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन नहीं हो पाया है और ऐसी ही स्थिति सड़कों की बनी हुई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार राज्य की भांति प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण का दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा किसी स्वतंत्र निर्माण एजेंसी को दिया जाए ताकि स्वीकृत सड़कों का निर्माण यथासमय हो सके और इन स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु रिवाइज्ड एस्टीमेट्स कमेटी गठित करने की आवश्यकता न पड़े।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की यह बहुत गंभीर समस्या है। यहां सड़कों का बनना बहुत आवश्यक है। मुझे जब अगली बार समय मिलेगा तब मैं आपके सामने सड़कों को विस्तारपूर्वक रखूंगा ताकि वहां पेय जल की समस्या का निदान किया जा सके।

MR. CHAIRMAN : You may continue next time.